



क्षेत्रीय विकास में उद्योग एक महत्वपूर्ण कारक

डॉ० डी० पी० एस रावत

भूगोल विभाग, के० जी० के० (पी० जी०) कालेज, मुरादाबाद (उ०प्र०), भारत

उद्योग:- उद्योग का तात्पर्य वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया से है। अतः विनिर्माण भूगोल का सम्बन्ध निर्माण, उसकी अवस्थापना एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों से है (Ropek, Howard GED. 1969) वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव तथा बेरोजगार के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के सन्तुलित एवं सम्यक विकास के लिए शिक्षित नवयुवकों को रोगार के अवसर प्रदान करना एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना एवं संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है।

उद्योगों का स्वरूप एवं क्षेत्रीय विवरण:- भारत एक कृषि प्रधान देश है जैसा कि अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड 'पवई' की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है जो पूर्णतया ग्रामीण है। यहाँ के नागरिक हथकरघा से वस्त्र बुनना, सूत कातना, बीड़ी बनाना, केकरी, बेकरी चलाना पटसन से बाघ बनाना, बिसाता के सामान बनाना, सीमेंट की जाली, पाइप, हौदे आदि सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा अन्य बहुत से छोटे-छोटे उद्योगों को अपनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार बैंको द्वारा कम व्याज पर ऋण देकर इन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग धन्धों को विकसित किया जा सकता है।

1. कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग:- अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य व्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसलिए कृषि यंत्रों से सम्बन्धित निर्माण उद्योग सेवा केन्द्र पवई, मिल्कीपुर, मित्तपुर, खैरुद्दीनपुर एवं बिलवाई में स्थित है। जिसमें पवई सेवा केन्द्र विशेष सक्रिय है। यहाँ कृषि कार्य हेतु हल, श्रेसर, पंखा, एवं अन्य छोटे-छोटे उपकरण विद्युत द्वारा संचालित लेन्स मशीन अथवा वेल्डिंग के माध्यम से बनाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि सेवा केन्द्र पवई, मिल्कीपुर, मित्तपुर में बड़ी राइस मिले तथा लगभग 25 छोटी-छोटी रइस मशीनें हैं एवं व्यक्तिगत धनकुट्टियों की संख्या 320 है। गेहूँ पीसने की चक्कियाँ 45 हैं, जो गाँवों एवं बाजारों में स्थित हैं।

2. गुड़ एवं खांडसारी उद्योग:- विकास खण्ड में गन्ने की खेती 31 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ गुड़ एवं खांडसारी उद्योग बहुत ही प्राचीन उद्योग है। ग्रामीण आज भी विद्युत चालित मोटर या डीजल चालित इंजन या बैलों से संचालित कोल्हुओं में अपना गन्ना पेरकर उसे गुड़ या खांड बनाकर बाजारों में बेचकर अच्छी मुद्रा प्राप्त करते हैं। जिसमें रबी की बुआई के बाद का उनके बेकार समय का सदुपयोग भी हो जाता है। गन्ना अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक फसल है।

3. बनाश्रित कष्ठ उद्योग:- अध्ययन क्षेत्रों आम, नीबू, बबूल, सागौन, महुआ, यूकेलिप्टस आदि वृक्षों की प्रधानता है। यद्यपि यहाँ व्यापारिक रूप से वनों पर आधारित बड़े उद्योगों का अभाव है फिर भी बढ़ई, लोहार इसको कुटीर उद्योग के रूप में अपनाएँ हैं जो विभिन्न सामानों को बेचते हैं। विकास खण्ड पवई में लगभग 11 आरा मशीनें हैं जहाँ लकड़ी की चिराई तथा फर्नीचरों का निर्माण भी होता है।

4. ईट निर्माण उद्योग:- क्षेत्र में पक्के मकान बनाने की तीव्रता के साथ-साथ ईट निर्माण उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ। इस समय अध्ययन क्षेत्र में कुल 10 भट्टे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुल मिलाकर लगभग 800 आदमी लगे हुए हैं। इस उद्योग में यहाँ के श्रमिक ईट पाथने, ढोने, लादने, उतारने में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश श्रमिक रॉची (झारखण्ड) से आते हैं। क्योंकि ये क्षेत्रीय श्रमिकों की तुलना में अधिक निपुण, कुशल, परिश्रमी, ईमानदार एवं सस्ते होते हैं। इस उद्योग के लिए कोयले की आपूर्ति मुगलसराय से होता है। यह उद्योग वर्ष में 4-5 महीने बरसात के कारण बन्द रहता है। जिसके कारण इसमें लगे लोगों को मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। भट्टा मालिक उन्हें उचित आर्थिक सहयोग देते हैं।

5 पशुधन पर आधारित उद्योग:- अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पशु संसाधन का बुनियादी महत्व है। विकास खण्ड पवई में प्रत्येक गाँव में 50 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि हेतु बैल एवं 80 प्रतिशत परिवारों के पास दुग्ध उत्पादन हेतु गाय-भैंस जैसे दुधारू पशु पाये जाते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक उपकरण जैसे- ट्रैक्टर आदि के उपयोग तथा बैलों की उच्च लागत के कारण लोगों को कृषि कार्य हेतु पशुओं पर निर्भरता कमशः कम होती जा



रही है। अन्य पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर आदि मुख्य है।

दुग्ध को पूर्ण आहार माना गया है। एक कृषक के लिए पशु इतना उपयोगी दूसरा जीव नहीं है। इससे वह दुग्ध एवं कृषि कार्य के अतिरिक्त खाद ईंधन आदि की भी पूर्ति करता है। कुछ गरीब कृषक जो गाय, बैस नहीं रख सकते या जिनका जागितगत पेशा है, वे भेड़, बकरियों पालकर उनसे दुग्ध प्राप्त करते हैं तथा भेड़ के बाल से ऊन बनाकर कम्बल बनाते हैं एवं बेचते हैं तथा मॉस हेतु उन्हें बेचकर अच्छी मुद्रा का अर्जन करते हैं।

6. मत्स्य उद्योग:- विकास खण्ड पर्वई के लगभग हर न्याय पंचायत में व्यक्तिगत पोखरे हैं जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन हेतु सरकार सस्ते व्याज पर ऋण भी दे रही है। कुछ ग्रामों में मत्स्य पालन विभाग आजमगढ़ द्वारा प्राप्त सहायता से मत्स्य उत्पादन व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। न्याय पंचायत रामनगर के कछरा ग्रामसभा एवं बागबहार के लारपुर ग्राम सभा में कहार एवं केवट जाति के लोग मत्स्य पालन ऊँचे स्तर पर कर रहे हैं। ये मछलियों से पैदा बच्चे पूरे क्षेत्र में बेचते हैं।

इस व्यवसाय में अध्ययन क्षेत्र के लगभग 250 लोग अपनी रोजी प्राप्त किये हैं। तथा मॉस हेतु उन्हें बेचकर अच्छी मुद्रा का अर्जन करते हैं। एवं उनका विक्रय करके अच्छी मुद्रा प्राप्त करते हैं। कुक्कुट फार्म भी विकसित है। कुटीर उद्योग के रूप में पशुपालन, मत्स्यपालन, के अतिरिक्त बढ़ई, लोहार, कुम्हार दर्जी आदि अपने परम्परागत व्यवसाय में लगे हैं। इसके अलावा यहाँ की मुसलमान जाति क्रेकरी, बेकरी, बीड़ी, अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि कुटीर उद्योगों में लगे हैं। जुलाहे हथकरघा बिसाता, मिठाई, डिब्बा, खिलौना आदि लघु कुटीर उद्योग अपनाकर अपनी रोजी चलाते हैं।

क्र.सं.	उद्योग	संख्या
1	कनीकर निर्माण	20
2	दुग्ध उत्पादन सहायकी समिति	80
3	ईंट भद्रता	10
4	लोहे की जाली एवं दरवाजा निर्माण	18
5	सावण मिल	18
6	इन्फोनिटोरिंग सर्विसेस	10
7	लकड़ी विप्लॉय केंद्र (आर. मजीन)	11
8	मत्स्य पालन	18
9	व्यक्तिगत दुग्ध उत्पादन केंद्र	12
10	मुर्गी फार्म	8
11	ब्लैट जाली निर्माण	8
12	अगरबत्ती	8
13	मोमबत्ती	4
14	बीड़ी	8
15	मैदा मिल	2
16	सूअर फार्म	2
17	शीत गृह	1

निष्कर्ष:- स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने विशेष ध्यान दिया। पिछले वर्षों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। जिनमें प्रथम संगठन (लघु उद्योग विकास संगठन 1954) का मुख्य उद्देश्य तकनीकी सलाह देना तथा द्वितीय संगठन (लघु उद्योग निगम 1955) का मुख्य उद्देश्य छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों के सहायतार्थ व्यापार कार्य चलाना था। वास्तव में कृषि क्षेत्र का विकास तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ही जनसंख्या के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। उद्योग में संलग्न उचित व्यक्तियों का प्रशिक्षण, ग्राम्य कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायक और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन इत्यादि प्रमुख हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jpnem W.D. & V.C. Frinch (1925): "Daitailed field Mapping of an agriculture area Annals" Assoc. Amer. Googrs 15.
2. Stamp L.D. (1931) : the Land utilization survey of Britain" Geographical Journal, 78 PP- 40-53.
3. Ramalingan, C. (1963) : "Some Economic Aspects of cropping pattern in India" vol. XVIII No. I - P-160
4. Ojha, R. (19683) : "Jansankhy Bhoogol" pratibha prakashan Kanpur p-131.
